हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही
10 मार्च, 2010
रूपन्द-1, अंक-4
अधिकृत विवरण

विषय सूची
बुधवार, 10 मार्च, 2010.

पृष्ठ संख्या

1. तालिका प्रदेश एवं उच्च (4) 1
2. नियम 48 (1) के अधीन सदन की भूमि पर रखे गये तालिका प्रदेश के लिखित उत्तर (4) 22
3. नियम 30 के अधीन प्रस्ताव (4) 32
4. विभिन्न विषयों का उद्यान जाना / व्यवस्थापन (4) 32
5. वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना (4) 34

110
श्री संपत सिंह : स्पीकर जी, मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए सरकार को कहना चाहता हूं कि इस्तेमाल में आने वाले स्टोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए, आगाज और स्टोन कैल्सियम के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। यह स्टोन कैल्सियम के उत्पादन में वृद्धि के कारण है और यह समस्त स्टोन कैल्सियम उत्तर प्रदेश में उत्पादन के हैं। अधिक महत्वपूर्ण है कि यह स्टोन कैल्सियम के उत्पादन में वृद्धि का कारण है।

प.व.ड. (बी & री) मिनिस्टर (श्री रंदीप सिंह सर्जेवाला) : सिर, उत्पादन में वृद्धि के कारण स्टील कैल्सियम के उत्पादन में वृद्धि का कारण है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>Year</th>
<th>Total Revenue collected from Minerals</th>
<th>Revenue collected from stone quarries</th>
<th>Number of stone quarries operated</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005-06</td>
<td>153.34</td>
<td>114.49</td>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>2006-07</td>
<td>136.26</td>
<td>105.33</td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td>2007-08</td>
<td>215.70</td>
<td>156.99</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>2008-09</td>
<td>195.24</td>
<td>144.72</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>2009-10</td>
<td>226.00</td>
<td>160.62</td>
<td>196</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*upto January, 2010*
श्री समप्र सिंह : अद्यावधि महोदय, मान्यता लहर 3 28 तारीख पढ़ाई है। एक ही माह से विश्लेषण, 2002 के बाद अन्तर्गत सुधीर कोट्स ने उन्हें जारी दिए थे उसके एक सम-स्टोन कैरियर except for two mines. एक निरीक्षण में और एक खैरी जनाशिध प्रभावकारिता में है स्थानीय 5 प्रकार, 2009 ने नवनिवास कोट्स एंड हाल ही है क्योंकि वे कार हो नीति की भीतरी थी। बाकी की सम-स्टोन का सब बना ही गया है। उसके बुन्द तारीख है जिसके बारे में हम जानते हैं मान्यता लहर 3 पढ़ाई है।

प्रमाण दोनों तो वापस उनकी लागू नहीं की है। एक ही माह से विश्लेषण में निरीक्षण के 3 अंश प्रमाण है क्योंकि जनाशिध प्रभावकारिता में है स्थानीय 5 प्रकार, 2009 ने नवनिवास कोट्स एंड हाल ही है क्योंकि वे कार हो नीति की भीतरी थी। बाकी की सम-स्टोन का सब बना ही गया है। उसके बुन्द तारीख है जिसके बारे में हम जानते हैं मान्यता लहर 3 पढ़ाई है।

विश्लेषण विश्लेषण में निरीक्षण के 3 अंश प्रमाण है क्योंकि जनाशिध प्रभावकारिता में है स्थानीय 5 प्रकार, 2009 ने नवनिवास कोट्स एंड हाल ही है क्योंकि वे कार हो नीति की भीतरी थी। बाकी की सम-स्टोन का सब बना ही गया है। उसके बुन्द तारीख है जिसके बारे में हम जानते हैं मान्यता लहर 3 पढ़ाई है।

विश्लेषण विश्लेषण में निरीक्षण के 3 अंश प्रमाण है क्योंकि जनाशिध प्रभावकारिता में है स्थानीय 5 प्रकार, 2009 ने नवनिवास कोट्स एंड हाल ही है क्योंकि वे कार हो नीति की भीतरी थी। बाकी की सम-स्टोन का सब बना ही गया है। उसके बुन्द तारीख है जिसके बारे में हम जानते हैं मान्यता लहर 3 पढ़ाई है।

श्री समप्र सिंह : अद्यावधि महोदय, मान्यता लहर 3 28 तारीख पढ़ाई है। उन्होंने सुधीर कोट्स का भी बदला दिया है। श्री समप्र सिंह : अद्यावधि महोदय, मान्यता लहर 3 28 तारीख पढ़ाई है। उन्होंने सुधीर कोट्स का भी बदला दिया है। श्री समप्र सिंह : अद्यावधि महोदय, मान्यता लहर 3 28 तारीख पढ़ाई है। उन्होंने सुधीर कोट्स का भी बदला दिया है।
श्री रणवीर सिंह सुरुवातीक: स्थिति सम्बन्धी नागरिकता के आधिकारिक है। तार पर स्थान पर इसने दिखाया है। इसकी स्थिति है और जो इसे देखा है उसके द्वारा में प्रभाव की जानना चाहते हैं। जो बीच में ज्ञान लिख कर दिखाया है उसमें ज्ञान सारणी नहीं देखा है और इसके संबंधी विषय सिद्ध कर सकता है। इसके कारण ऐसे विषय संबंधी विषय की स्थिति आदरणे के अंदर थी जो उस समय देखा जाता था। इसकी स्थिति है और जो इसे देखा है उसके द्वारा में प्रभाव की जानना चाहते हैं। जो बीच में ज्ञान लिख कर दिखाया है उसमें ज्ञान सारणी नहीं देखा है और इसके संबंधी विषय सिद्ध कर सकता है। इसके कारण ऐसे विषय संबंधी विषय की स्थिति आदरणे के अंदर थी जो उस समय देखा जाता था। इसकी स्थिति है और जो इसे देखा है उसके द्वारा में प्रभाव की जानना चाहते हैं।
Mr. Speaker: Is it the way Arora Sahab? You are standing here and you are happy. (Mention)

Bhai Sardool Singh Ji,enter: at this time, Bhai Sahib ji's father, Mr. Sardool Singh Ji, is the senior and respected leader. He has brought up many fishermen in the village and has played a significant role in the development of the village. (Mention)

Mr. Speaker: It is for the first time that any State has taken up a holistic approach to address the concerns arising on account of mining operations on a long-term basis. The State Government has taken a number of important decisions in this direction. These are:

i) A decision was taken at the level of Council of Ministers in its meeting held on 21.08.2009 to ban mining of major minerals in the districts of Faridabad and Mewat for a period of 10 years;

ii) A decision to undertake State controlled mining of construction material over a limited area of 600 hectares in the district of Faridabad out of total mineral bearing area of 6700 hectares, and 1500 hectares in the district of Gurgaon and Mewat out of the total mineral bearing area of approximately 23000 hectares following extensive discussion and consensus with the CEC;

iii) Notified a ‘Scheme of Mining’ for the district of Gurgaon and Mewat (which will also be extended to district of Gurgaon and Mewat) consisting of the detailed guidelines for grant of mining contract/leases, establishment of an ‘Aravalli Rehabilitation Fund’ and constitution of a Monitoring Committee to monitor that the mining operations over the limited areas are carried out in compliance of the EMPs for these areas:
श्री अख्तव : यह साधन सम्बन्ध हो गया। इतना ही काफी है।

श्री रन्देप सिंह सूरजेवाला : सर, तो आप ने किसी बात से बताया है कि लेखने का बड़ा है। ऐसा नहीं जी था। इतना ही काफी है।

श्री रन्देप सिंह सूरजेवाला : पहले देखकर सर, नंदी जी ने कहे हैं तो हम नियत कर देंगे कि लेखने का बड़ा है। लेखने का बड़ा है। इतना ही काफी है।

श्री रन्देप सिंह सूरजेवाला : पहले हमारे से आपको बताया गया कि लेखने का बड़ा है। इतना ही काफी है।

श्री रन्देप सिंह सूरजेवाला : पहले हमारे से आपको बताया गया कि लेखने का बड़ा है। इतना ही काफी है।
श्री कृष्णचंद्र गुप्तराय: आज्ञा गयोर, मैं आपके माध्यम से भादीय गंगी जी के पुनः वायुगा कि उन्होंने कहा है कि सुधीर कोट्स के आदेश के लिए वे खाने वाला कदम की गई है। सुधीर कोट्स के आदेश के बाद आप अपने जानने में कितनी गंगी दी हुई है, जिन्हें मुझसे कर्त्ता हुई है इस बार से हम सभी जी भरते हैं। दूसरा नेता प्रस्तुत भी है कि सुधीर कोट्स ने आदेश दिए उसके बाद फॉरेस्ट एरिया में किसी चांद जरूरत में सुधीर कोट्स के आदेशों के अनुसार कितनी दी हुई है और यहाँ निर्माण युद्धगांव और फोरेस्ट एरिया में कितने हैं? इस बारे में मंदी जी बताते।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is also a separate question. So, a separate notice needs to be given.

श्री विमलप्रसाद चोनी: आज्ञा महेश, मैं आपके माध्यम से मंदी जी की से जानना चाहता हूँ कि क्यों वे देश और धन्य की वेतन दिये गए आपके संबंध होता तो देखता हूँ यह लेने है और देखता उस देश और धन्य की वेतन देने का क्या पता है? लेकिन यह किसने किसने की जमीन से वह रेता उठाया जाता है उसकी जमीन का है इस बारे में मंदी जी बताते?

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is also a separate question. So, a separate notice needs to be given.

पहले समय सिंह: क्या समझते हैं, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं आया इसलिए मुझे प्रश्न करने का रा रहा है। मैंने कहा था कि दुरुस्ती कोट्स को आदेश देना चाहिए। दुरुस्ती कोट्स को सही बनाने के लिए एक नए प्रयास करना चाहिए। राजीव की नजर तो मैंने नहीं दिखाई दी है इसके लिए दुरुस्ती कोट्स को सही बनाने के लिए एक नए प्रयास करना चाहिए। दुरुस्ती कोट्स को सही बनाने के लिए एक नए प्रयास करना चाहिए।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is also a separate question. So, a separate notice needs to be given.
Construction of New Road

18 Shri Krishan Lal Panwar: Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new road from Village Satana, Distt. Panipat to Thermal Plant upto Kasauni Road. If so, the time by which the said road is likely to be constructed?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): No, Sir.
Construction of Swimming Pool

* Dr. Hari Chand Midha: Will the Chief Minister be pleased to state whether any announcement to construct a swimming pool at Jind was made by the Hon'ble Chief Minister five years ago; if so, the time by which the said swimming pool is likely to be constructed?
P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir. However, the announcement for constructing the swimming pool at Jind was made on 11/01/2007 and not five years ago.

The swimming pool is expected to be constructed within a period of two years.

Mr. Anand Sharma, in his question, said that if the condition of the swimming pool is such that it cannot be used due to a lack of maintenance, it is not true. Although the condition of the swimming pool may have deteriorated, it is not true that it cannot be used. The Swimming pool is expected to be completed within two years.

Maintenance of War Memorials

Col. Raghbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War Memorials installed at various places in the State; if so, the details thereof?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes Sir, expenses on maintenance and upkeep of War Memorials are being met from Haryana Defence and Security Relief Fund.

A sum of Rs. 19,40,08/- has been spent on maintenance and upkeep of War Memorials from Haryana Defence and Security Relief Fund so far.

Shri Randeep Singh Surjewala: The Chief Minister may be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War Memorials installed at various places in the State; if so, the details thereof?

Shri Randeep Singh Surjewala: The Chief Minister may be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War Memorials installed at various places in the State; if so, the details thereof.

Col. Raghbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War Memorials installed at various places in the State; if so, the details thereof?
"Bhiwani is the Biggest district in terms of strength of Ex-servicemen and area. The district also pioneers when it comes to Warriors and gallantry awards which is a matter of pride for one and all in the district. Every district has a war memorial to commemorate the heroes of the society and the district. Regrettably the war memorial at Bhiwani is not befitting the sacrifices made by its heroes."

Shri Ram Dutt Singh : Shri Ram Dutt Singh is a long-time resident of Bhiwani. He took a stance against the existing memorial and called for a new one that reflects the true spirit of sacrifice.

Shri Bhupinder Singh : Shri Bhupinder Singh is a former soldier who served in the war. He believes that the memorial should be a tribute to those who sacrificed their lives for the country.
श्री अवज्ञ : दिनेश सहाय, मैं आपकी वार को मानता हूँ कि शीरिजलूकी लेना चाहिए। (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)

श्री रंदीप सिंह सुरजवाला : तार, सहीहों का समानांतर और इस वेयर के लणि उदयरे, विवाद का या रणनीतिक मामला के प्रभाव ही नहीं हो सकती है। किन्तु यह वार, जब तक वह ने यह ईद प्रकाश दिनराते का उपयोग नहीं किया तब तक वह शीरिजलूकी नहीं कर सकता। क्योंकि नहीं, तब तक वह ने यह ईद प्रकाश दिनराते का उपयोग नहीं किया तब तक वह शीरिजलूकी नहीं कर सकता।

श्री अवज्ञ : आग्नेय महोदय, 1857 में .......... (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I am trying to answer, this is not the way, Sir.

Mr. Speaker : He is replying your question. Mr. Vij, let him reply (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)

श्री रंदीप सिंह सुरजवाला : सर, वर विज साहब क्या चाह छोटे हुए, या दोस्त कर पाए और मैं वेद गया। मैंने उन्हें कोई लेखने के लिए उनके पत्र दिखाने का समय दिखाया तब तक वे अपनी शर्मा ने नहीं, इतने जब उन्हें हल्की अपनी शर्मा करते साथ जब तिरस्कर करते नहीं थे। हूं की बात सर, विज साहब में कहीं कहीं अश्वान है और मैं भाषा विषयों को शीर्षक भी हैं और वह कहते हैं। इसके बाद वे चाहते थे कि श्री और वह बाद को शीर्षक भी है। उन्हें यह नहीं नहीं, कहते चाहते। (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)

श्री अवज्ञ : आग्नेय महोदय, 1857 में नहीं है। (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he is interrupting me. This is not the way.

Mr. Speaker : This is not possible. Vij Sahib. I allowed you to speak. Now, let him give his reply.

श्री अवज्ञ : आग्नेय महोदय, इस मामले में तो सीतिशक्ति नहीं होनी चाहिए। (श्री रंदीप सिंह सुरजवाला)
Shri Randeep Singh Surjewala : This is not a matter of politics. This is a matter of war memorials. You have already made your point. I am trying to say something with the permission of the Chair. (Interruptions) We have to have decorum, decency and mutual respect. यह बात तुम्हारे मायने में नहीं होगी क्योंकि तुम अपने को लेकर ही तुम इसी बात के लिए माननीय रुप से पूरा कर रहे हो जो तुम्हारे नाम के लिए मैं कहा जा रहा हूँ। 1987 में, आपने तुम्हारे नाम के लिए सभी दुनिया के लिए गद्दी में बैठक कर आपकी समस्या या किसी और तरह के मुद्दे का समाधान करने के लिए उपलब्ध थे?

मुख्यमंत्री (भी नैना सिंह नहरु) : आपका अनुमान अपने मायने में नहीं होगा। तुम सब कुछ को समझते हो। जब उन्होंने जीवन जीने के मायने में कहा, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि तुम उन्हें इस तरह से समझा हो। इन्हें समझना पड़ेगा कि तुम उन्हें इस तरह से समझा हो।

भीनी (मोदी सिंह भूजिया) : वहाँ गतिविधि के लिए तुम भी कहते हो कि तुम सभी दुनिया के लिए उपलब्ध थे। उन्हें समझना पड़ेगा कि तुम उन्हें इस प्रकार से समझा हो।

श्रीधर हरमन (धर्मशाला) : तुम सभी दुनिया के लिए उपलब्ध थे। तुम उन्हें समझना पड़ेगा कि तुम उन्हें इस प्रकार से समझा हो।
Property of Haryana Wakf Board

* 102 Shri Aftab Ahmed: Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the district-wise total property of Haryana Wakf Board in the State;
(b) whether whole of the property is in the possession of Wakf Board together with the details of the property in illegal possession;
(c) the steps being taken to vacate property from illegal possession; and
(d) whether there is any proposal for providing lands for graveyards in the villages and towns in the State of Haryana where Muslim population resides and there is no Wakf Board property exists?

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Sir, the details of district-wise properties of the Haryana Wakf Board are placed on the table of the House as Appendix-I.
(b) No Sir. The details are placed on the table of the House as Appendix-II.
(c) The Board has filed suits for possession in the Courts for vacation of Wakf properties from illegal possession. Presently, 447 such suits are pending in various Courts. Details of the same are appended as Appendix-III. Besides, there are 189 cases in which the Board has issued notices under Section 54 of the Wakf Act, 1995 against illegal occupants/encroachers and in 24 cases, after conducting proper enquiry, the Chief Executive Officer of the Board has already passed order against the encroachers under Section 54 (3) of the Act and referred to the concerned Sub Divisional Magistrates under Section 55 for execution. For rest of the properties, the action is being taken.
(d) At present there is no policy. However, each case will be considered by the Government on receipt of proposal.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Sr. No.</th>
<th>District</th>
<th>No. of rural properties</th>
<th>No. of urban properties</th>
<th>Total No. of rural &amp; urban Wakf properties</th>
<th>Area of rural Wakf properties as per Gazette notification</th>
<th>Area of urban Wakf properties as per Gazette notification</th>
<th>Total area of Wakf properties</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Kms</td>
<td>Marla</td>
<td>Sq. Yds</td>
<td>Kms</td>
<td>Marla</td>
<td>Sq. Yds</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ambala</td>
<td>689</td>
<td>385</td>
<td>1075</td>
<td>8960</td>
<td>3</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Panekela</td>
<td>72</td>
<td>29</td>
<td>101</td>
<td>2715</td>
<td>10</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kuranakshetra</td>
<td>697</td>
<td>285</td>
<td>982</td>
<td>16450</td>
<td>15</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kanaj</td>
<td>412</td>
<td>309</td>
<td>727</td>
<td>7472</td>
<td>9</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Paripat</td>
<td>296</td>
<td>675</td>
<td>971</td>
<td>4690</td>
<td>12</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Sonipat</td>
<td>359</td>
<td>419</td>
<td>769</td>
<td>3056</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Faridabad/Palwal</td>
<td>335</td>
<td>213</td>
<td>549</td>
<td>4541</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Gogona</td>
<td>202</td>
<td>44</td>
<td>206</td>
<td>1601</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Mewat(Nuh)</td>
<td>597</td>
<td>234</td>
<td>2211</td>
<td>32151</td>
<td>8</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Rewari</td>
<td>171</td>
<td>82</td>
<td>253</td>
<td>1954</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Mohindergarh</td>
<td>96</td>
<td>252</td>
<td>330</td>
<td>823</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Rohak</td>
<td>161</td>
<td>135</td>
<td>295</td>
<td>1767</td>
<td>15</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Jhajjar</td>
<td>178</td>
<td>108</td>
<td>286</td>
<td>2096</td>
<td>5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Jind</td>
<td>345</td>
<td>80</td>
<td>425</td>
<td>2549</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Sirsa</td>
<td>362</td>
<td>161</td>
<td>523</td>
<td>8961</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Puthakbad</td>
<td>269</td>
<td>47</td>
<td>316</td>
<td>8762</td>
<td>19</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Hisar</td>
<td>397</td>
<td>507</td>
<td>904</td>
<td>5388</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Bhilwara</td>
<td>263</td>
<td>123</td>
<td>386</td>
<td>3480</td>
<td>14</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Kothal</td>
<td>379</td>
<td>162</td>
<td>541</td>
<td>6886</td>
<td>18</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Yamuna Nagar</td>
<td>525</td>
<td>58</td>
<td>583</td>
<td>4883</td>
<td>17</td>
<td>19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Grand Total** | **8184** | **4369** | **12493** | **129183** | **189** | **118** | **37980** | **199** | **186** | **167153** | **168** | **304**
## Appendix-II

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sr. No.</th>
<th>Name of District</th>
<th>No. of Wakf properties in the possession of Wakf Board</th>
<th>No. of properties under encroachment</th>
<th>Grand total of column No. (3) &amp; (4)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ambala</td>
<td>1019</td>
<td>56</td>
<td>1075</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Panchkula</td>
<td>79</td>
<td>22</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Yamuna Nagar</td>
<td>580</td>
<td>3</td>
<td>583</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Kurukshetra</td>
<td>911</td>
<td>71</td>
<td>982</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Kaithal</td>
<td>530</td>
<td>11</td>
<td>541</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Hisar</td>
<td>745</td>
<td>159</td>
<td>904</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sirsa</td>
<td>460</td>
<td>63</td>
<td>523</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Fatehabad</td>
<td>296</td>
<td>20</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Bhiwani</td>
<td>312</td>
<td>74</td>
<td>386</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Karnal</td>
<td>702</td>
<td>25</td>
<td>727</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Panipat</td>
<td>944</td>
<td>27</td>
<td>971</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Sonepat</td>
<td>640</td>
<td>129</td>
<td>769</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Rohtak</td>
<td>218</td>
<td>77</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Jhajjar</td>
<td>189</td>
<td>97</td>
<td>286</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Gurgaon and Mewat</td>
<td>2428</td>
<td>29</td>
<td>2457</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Faridabad and Palwal</td>
<td>532</td>
<td>17</td>
<td>549</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Rewari</td>
<td>249</td>
<td>4</td>
<td>253</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Mohindergarh at Narnaul</td>
<td>324</td>
<td>26</td>
<td>350</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Jind</td>
<td>422</td>
<td>3</td>
<td>425</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td></td>
<td><strong>11580</strong></td>
<td><strong>913</strong></td>
<td><strong>12493</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

*About 450 Acre Wakf lands are under encroachment. Exact area under encroachment is being worked out by demarcation.*
### Appendix III

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sr. No.</th>
<th>Name of the District</th>
<th>Suit for possession filed by the Board</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ambala</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Yamuna Nagar</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kurukshetra</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Rewari</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Hisar</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Bhiwani</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Sirsa</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Jind</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Tohana</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Kaithal</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Karnal</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Panipat</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Sonepat</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Rohtak &amp; Jhajjar</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Palwal &amp; Faridabad</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Gurgaon/Mewat</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Total cases** 447
बोर्ड अपने केल हर जाता है और बालिकें पार्टी भीतर जाती है? बालिके पार्टी को एक बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने से काफी फायदा हो जाता है। हां, इस बोर्ड का विदेश इस मूल्य में बढ़ा लेता है।

भी रचनी दिया सुकुल नेत्र: अब नहीं, मैं माननीय सदरमैल आयोग के सदस्य जी की बिना के साथ अपने आपको भी लोकत्यो है। यह सच है कि वक्त बोर्ड की बालिके की बैठक में नजर रखने वाले भी नजर रखने वाले भी देख रहे हैं कि वक्त प्रातिरिक्य पर इतरीतिर्यक्त एक्शन प्रस्ताव तो भी है और तब पर इके किस्म कार्यवाही गई हो रही है। हमने यह सबसे पहले हरियाणा वक्त बोर्ड का घोषणा उसका लिए ध्यान देने के लिए आत्मा कर दिया है। वहाँ वाले ने इसके प्राप्त नहीं गई है उसके घोषणा आईवेंडिफाइड, बड़े उनके प्राप्त इस रूप से ऐसा अच्छा है। जल्दी सक दिन्दिनेंद्र की अनुमति है हमने उतसके लिए बाकीदाई एक-एक बिल ले रहे थे। इसलिए विदेश की दिघिस्तान विदेश की उनके खर्च में साधन है। भी आपकी भावना भी माननीय सदरमैल की सदन को बताना चाहिए कि हम बन सके से बचक वक्त प्रातिरिक्य की ताकत को लेकर लड़ाई है। जहाँ वे माननीय सदन की लाइन को कोई अधिकारिक कानून रख रहा है तो हम बताएँ।

भीम नेत्र: भी माननीय सदरमैल है यह हमने बताएँ। वह सबसे भी माननीय सदनी जी से भाषण का अनुभव है कि वे एक निश्चित बालक को लेकर लड़ाई है। अभी नहीं, मैं अपने द्वारा माननीय नेत्री जी से हमने भाषण का अनुभव है कि वह सबसे भी माननीय सदनी जी की कानूनी कार्यवाही करने का जड़ रख रहे हैं।

भी माननीय सदरमैल: अब नहीं, मैं जीता लाल ने 'स्की' पार्टी के अंदर में बताएँ कि ये कैसे हो बच्चे को लेकर लड़ाई है और दोनों के कार्यक्रम के द्वारा उनका नवीनिता का रूप है। माननीय नेत्री जी के लिए हमने इसको अपना करते हैं कि हमने इसके लिए शुरुआत की है।
श्री आचार्य : आप रीति में कहें। Don’t give the speech.

चौथी मोहम्मद इलिशाश्व : अब्बास महोदय, 600 वर्ष गगन जमीन हिसाब के बंदर है। इसी तरह से यहुदी भारत के अंदर स्थाना रोक देने वाले होते, वर्ष नं 23 में भी जमीन है।

श्री आचार्य : यह यह पोषण है कि हर एक लोकों का हमला दिया जाए तो आप राजबंद बिजली पूरी हो।

चौथी मोहम्मद इलिशाश्व : सर, मैं निजी रूप से कह रहा हूँ। इसलिए मुझे के अंदर राजवंश में भी नहीं संबंधित देखा है जो मुसलमानों की रहस्य है। इसी तरह से जनवर से जनवर ही गोरे गहराई नहीं है जहां पर काफी सुधार होते है। काफिया का अंदर भी बहुत सुधार होते हैं।

श्री आचार्य : आप तो सारे स्टेट पर आ आए। इस वर्ष का जन्म इतिहास देखा जा सकता है इसलिए आप इसी वर्णन के देखा है।

चौथी मोहम्मद इलिशाश्व : सर, जहां सुधार आवश्यक है वहां पर कविता के लिए मुसलमानों के पात्र फर्द नहीं है। यह माननीय मंत्री का इससे कोई विचार है कि उनके कविता के लिए जाना दी जाएगी? सरकार सर, वह मंत्री जो बताते है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो देखा पर राजवंश के लिए पागह नहीं है वह पता के लिए सरकार के पात्र कोई प्रतिबंध निरापद नहीं है कि उनका कविता के लिए जाना दी जा जाएगी?

श्री जयनीता सिंह सुरेशराव : धीरेर सर, माननीय सदस्य श्री आचार्य अब्बाद जी ने वह सुनात लक्षात्मक करने वाला लोगी वहीं पर स्थितियाँ यूथ है से और उसका अंदर विवादित जवाब दे दिया है, इस सत्ता के दोनों माननीय सदस्य प्रद देखा है वहीं जीवन नहीं}

चौथी आचार्य अब्बाद : अब्बास महोदय, सर आपके माननीय सदस्य मंत्री जो दो जानने काफी है कि हमने यहाँ कूच किसी भी अधिकारियों नहीं है, उनमें से फर्दुस और पादशाह में हमारी कविता के लिए बूढ़ी की बात बिख़रे भी हटते हैं और वहां कविता सरकार को जाना दो दिन तक नहीं है। उनके माननीय मंत्री महोदय से निरीक्षण करके कि उसमें जाना देशी जानी की अद्यावधारित करके सरकार के लिए सो जाना मे है वह भी सरका से अपना कर है।

श्री जयनीता सिंह सुरेशराव : जब तक कविता के लिए जमीन देने की व्यवस्था करने का प्रयास है जैसा जमीनी सदस्य श्री मोहम्मद इलिशाश्व जी ने कहा या श्री आचार्य अब्बाद जो ने कहा। इस बारे में मैं सही बात कहने कि यह डिमांड बिल बिच में विवाद का प्रद दो है। हमने कहा कि वह कोई एक स्टूटरी संदी की है और कविता के लिए जाना भी जमीन है यहाँ हम देने के लिए दिखाई है। आप अगर हैं कि वह कोई जमीन नहीं है तो वे इतिहास के मुख्यमंत्री सुखित करते हैं कि जब हम हमारे माहौलरिताज के नामों के लिए कविता की आमंत्रण करते है उनके लिए नए परिवर्तन या विकास के गामें से या किसी भी विवाद की जमीन हो, तो हम जमीन सोचकर करना का प्रयास करते हैं। स्थितियाँ इंटरनेट अभिव्यक्ति भेजने दी है हम उसकी जानें करना के सुनिश्चित करने कि उसका हम निकाल सकें।
Upgradation of Schools

86 Shri Sher Singh Barshami: Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the total number of Primary, Middle and High schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and

(b) whether there is any proposal under consideration to upgrade the Primary to Middle, Middle to High and High to Secondary schools during the current and next financial year 2010-2011?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhil):—

(a) Sir, the total number of schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1.4.2005 till date are: Primary School to Middle School twenty five; Middle School to High School one; and High School to Senior Secondary School two.

(b) The upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of schools in Ladwa Assembly Constituency would be considered after finalisation of revised norms.

Shri Bher Singh Badarni:— The Hon’ble Minister of Education, in reply to the question raised by Shri Sher Singh Barshami has stated that the number of schools upgraded in the Ladwa Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 till date is as follows:

- Primary School to Middle School: 25
- Middle School to High School: 1
- High School to Senior Secondary School: 2

Shri Bher Singh Badarni:— The Hon’ble Minister has stated that the upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of schools in Ladwa Assembly Constituency would be considered after finalisation of revised norms.

Geeta Bhukkal Matanhil:— The Hon’ble Minister has stated that the upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of schools in Ladwa Assembly Constituency would be considered after finalisation of revised norms.

Shri Bher Singh Badarni:— The Hon’ble Minister has stated that the upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of schools in Ladwa Assembly Constituency would be considered after finalisation of revised norms.
Smt. Kiran Chaudhary: Mr. Speaker Sir, I would like to request the Hon’ble Minister that in her reply she has said that the up-gradation norms of schools are under revision and further up-gradation schools will be considered after the finalization of revise norms. As you know well Sir, that education is one of the primary sectors of our Government. That is why, the Government School attach great deal of priority to it. I would like to ask the Hon’ble Minister when these revise norms are going to be finalized and what is the time bound period? Secondly Sir, she had announced that in every block model schools are going to be put in. So, I would also like to ask her through your goodwill by what time these model schools will also be started.

Smt. Geeta Bhukkal Matanhai: Speaker Sir, I would like to tell the Hon’ble member as per the revising norms that the school building having more than one storey should provide one ramp and stair case at least six feet width. The reason to revise these norms is because the Right to Education Act is going to be implemented from 1st April, 2010. So Data regarding the up-gradation of schools from the Primary to Middle, Middle to High and High to Senior Secondary schools have been analysed during 2009-10 and after examining it was found that the up-gradation of these schools are highly swept. The data clearly shows that in some of the places numbers of the schools have been upgraded and in some of the places number of the schools up-gradation were less that’s why we have decided that this policy regarding the revision of norms will be finalized by 30th of April, 2010. Sir, second query she has asked about the model schools. As we are considering and cases are pending, we will decided it.

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, I just wanted to know from the Hon’ble Minister as the concerned minister has not replied my question.

Mr. Speaker: Please take your seat.

Sr. रोटेटी सिंह सुभाषी: आपका भविष्य, न मनों जो ते जानना चाहता हू ह कि जो स्कूल पर अप्रैल 2005 से आत तक अप्रैल 2010 का कार्तिकिया कुशलित वर्तने का, वह जो वाला स्कूल आप राहत कर दिए गए है या जो की कार्तिकिया कुशलित कहते है उनको आप राहत की जातीय या नहीं की जातीय?

Sr. मिती शिशु बुधकल मातनहट: तीसरी सार, इसकी लागू कार्तिकिया कुशलित के अनुसार जी स्कूल अप्रैल 2010 के लिए मिती है उनको नई रिखाईप सार सुनने के बाद टेक यह करने। अगर आपकी
हमारे पास स्कूल अपोषेत्रण की रचनीकर्ता या रिफरेंस आई है और वे सभी पूरी करते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा।

श्री शेख शहीद बदरानी: स्पीकर सर, मैं गंजी जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या समय अपोषेत्रण के लिए जो क्राइटिकल लागु है और क्यों नहीं। उसमें लिखा है कि यह क्राइटिकल है तो क्या पूरा करते हैं तथा वह निष्क्रिय अपोषेत्रण किया जाएगा या नहीं।

श्रीमती रीता मुश्कल बाहानेश्वर: स्पीकर सर, भी माननीय सदस्य ने बताया कि इस समय अपोषेत्रण के लिए जो क्राइटिकल लागु है और क्यों नहीं। अपोषेत्रण के लिए जो क्राइटिकल है तो क्या हुआ है या नहीं। वह क्राइटिकल है या नहीं।

श्री अरविंद शुभांगा अरविंद: स्पीकर सर, लाइब्रे के बाल के स्कूल क्राइटिकल लागु है तो क्या यह करते हैं या नहीं। उन्होंने भी क्राइटिकल किया जाएगा।

श्रीमती रीता मुश्कल बाहानेश्वर: स्पीकर सर, लाइब्रे के बाल के स्कूल क्राइटिकल लागु है तो क्या यह करते हैं या नहीं।

श्रीराम गंजी जी: क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

श्रीमती रीता मुश्कल बाहानेश्वर: स्पीकर सर, मान्यता के अनुसार उसमें बाल के स्कूल क्राइटिकल लागु है तो क्या हुआ है या नहीं।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

विपन्नाचार्य विभाग का अनुसार यह क्राइटिकल लागु है तो क्या हुआ है या नहीं।

विपन्नाचार्य विभाग का अनुसार यह क्राइटिकल लागु है तो क्या हुआ है या नहीं।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

श्री सुश्री मणि कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, लाइब्रे के बाल के स्कूल क्राइटिकल लागु है तो क्या यह करते हैं या नहीं। उन्होंने भी क्राइटिकल किया जाएगा।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

श्री सुश्री मणि कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, लाइब्रे के बाल के स्कूल क्राइटिकल लागु है तो क्या यह करते हैं या नहीं।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।

मिस्ट्री स्कूल क्राइटिकल लागु है क्या हुआ है या नहीं।
[भीमती हिन्दु स्वाधीनता]
कि क्या विक्रमिलान के विवाद में स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा या पारित आवेदन में से स्कूलों को अपग्रेड करती है? यह भी जानना चाहिए कि को स्कूल नाम है जो पारित डिटॉर्म नहीं किया जायेगा?

[भीमती हिन्दु सुब्रकन माननेवालः] अग्रदृश्य में आपके समय से माननीय सदस्य को बताना चाहिए कि upgradation depends on case to case और जो भी स्कूल है जो अपग्रेड करता है उसके लिए हमें फाइनेंस विभाग में पुस्तक लेनी होती है।

Mr. Speaker: Now the Question Hour is over.

**नियम 45 (1) के अनुसार सदन की मंजूरी पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिहित उत्तर**

**Upgradation of Schools**

* 185. Shri Ramashwar Dayal: Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the total number of Primary, Middle and High schools upgraded in Bawal Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and

(b) whether there is any proposal to upgrade Primary to Middle, Middle to High and High to St. Secondary School level during the current and next financial year 2010-2011.

[शीखा मन्त्री] (शीखा मन्त्री मुकुल माननेवालः):

(अ) शीखा जी, बावल में 1-4-2013 तक पारित निर्देशनों द्वारा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय -

(ब) विद्यालयों को स्तरोत्तक करने के बाद विद्यालयों की संख्या में कमी हुई है। बावल में विद्यालयों निर्माण क्षेत्र में विद्यालयों को, स्तरोत्तक करने के बाद विद्यालय संख्या कम हो गई है।

**Punjabi as Second Language**

* 76. Shri Ashok Kumar Arora: Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the details of the notification declaring Punjabi as the second language of the State;
(b) whether this notification fulfills all the required conditions under the law; and
(c) if the answer to (b) above is in affirmative, then what is the status of Telugu language in the State?

शिक्षा ग्रहण (श्रीमती गिरी गुप्ता मुख्य मालिक हैल) :-

श्रीमती जी

(क) अधिकृतता की एक प्रति रचना के पतला पर रखी गई है।
(ख) यह हैं।
(ग) ग्रहण के (घ) एवं (घ) भाग पार्चनिक अस्थायी है।

अधिकृतता

हरियाणा सरकार

शिक्षा एवं भाषा विभाग

दिनांक 28 जनवरी, 2010

संपत्ता 1/60-2010 शासन(2)---हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1989 की धारा 3 की स्पष्टता
(2) द्वारा प्रदत्त माहौल का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा ही से पूर्वबंद
शासनीय प्रतिष्ठित में उपवास किए जाने के लिए प्रत्यक्ष माहौल को द्वितीय माहौल के रूप में निर्देशित
किया है।---

(i) राज्य सरकार तथा इसके कार्यालयों द्वारा पंजाबी माहौल में प्रतिवेदनों को प्रदान करके
शासन
(ii) पंजाबी माहौल तथा पंजाबी शासन को बढ़ावा देना।

राजभाषा,

विश्वास एवं भाषा सर्विस, हरियाणा सरकार,

शिक्षा तथा भाषा विभाग।

*125. **Smt. Sumita Singh**: Will the Environment Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to preserve the environment in the state; if so, the detail of scheme?

**Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav)**: Yes Sir. The detail of the scheme under consideration of the Government are laid on the table of the House.
Detail of Schemes

Government of Haryana have been implementing various schemes for the preservation of environment in the State. At present 5 new schemes are under active consideration of the State Government:-

1. **Introduction of Green Buildings concept.**

   The Environment Department is considering to issue a notification making adoption of the green building concept compulsory for buildings occupying a prescribed minimum floor area/plot area. Action has been initiated to prepare a ‘Green Manual’ for the State.

2. **Preparation of Environmental Action Plan for the Towns of Faridabad and Panipat.**

   The Central Pollution Control Board has conducted a survey of 89 selected Industrial areas/Clusters with the help of IIT Delhi and developed a Comprehensive Environmental Pollution Index (CEPI). Faridabad comes at serial No. 18 and Panipat comes at serial No. 37 in this list of 89 industrial areas/Clusters in descending order of CEPI. The State Government has initiated the preparation of remedial action plan for these two towns to restore their environmental quality.

3. **Improved System for the disposal of Bio-Medical Waste.**

   Since it has been found that present arrangement for Bio-Medical Waste disposal is not satisfactory, the Department of Environment has initiated action to prepare a more effective plan of action in consultation with the Health Department.

4. **Safe disposal of used/fused and disposed of compact fluorescent lamps (CFL).**

   The Department of Environment has initiated action to prepare a plan for collection and disposal of used/fused and disposed of Compact Fluorescent Lamps (CFL), with the help of the Municipal Committees.

5. **Restructuring of Haryana State Pollution Control Board.**

   It is felt that with the increased emphasis on environment, there is need for strengthening of the Haryana State Pollution Control Board. The Board is preparing a restructuring plan accordingly.

---

**Crime Against Women**

*83. Shri Ajay Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the yearwise total number of cases registered relating to Crime against women, for the period 2001 to 2009; and*
(h) the yearwise number of case registered, for the crime of female
foeticide during the period 2001 to 2009?

नुक्सानन्दी (भी मुहेंद्र सिंह ठुढळा): टालकिस तृत्यग लोक सभा के बिटल पर रखी जाती है।

नुक्सान

विश्व (क)

महिलाओं के विरुध्ध अपराध से सामने आए बर्ज भूखने

<table>
<thead>
<tr>
<th>अपराध का वर्ष</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>महिलाओं के नंबर</td>
<td>3391</td>
<td>4383</td>
<td>4132</td>
<td>4160</td>
<td>4107</td>
<td>4860</td>
<td>5756</td>
<td>5095</td>
</tr>
</tbody>
</table>

विश्व (ख)

कन्या भूख हल्ला के वर्ज भूखने

<table>
<thead>
<tr>
<th>अपराध का वर्ष</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
<th>2005</th>
<th>2006</th>
<th>2007</th>
<th>2008</th>
<th>2009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>कन्या भूख हल्ला</td>
<td>26</td>
<td>25</td>
<td>29</td>
<td>38</td>
<td>44</td>
<td>47</td>
<td>30</td>
<td>45</td>
<td>44</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**To Regularise Jhuggi/Basties**

*92. Shri Krishan Pal Gurjar: Will the Urban Local Bodies Minister be
pleased to state—*

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government
to regularize the Jhuggi/Basties of Faridabad; If so, the time by which
these Jhuggi/Basties are likely to be regularized: and

(ב) whether there is any proposal under consideration of the Government
to start development works in the above said Jhuggi/Basties?

विज्ञानी मंत्री (भी महेंद्र प्रदाप सिंह):

(वी) सगर परिसर, फरीदाबाद, फरीदाबाद में भूगूंद्री निवासियों को नूनसनिक्षित / नूनसनिक्षित
kरण के लिए जोवीराइज रॉयल विलेज आ रहा है।

(वि) उपरोक्त ‘क’ के दृष्टिकोण, भूगूंद्री / विकास चार्टियों में विकास कोर्ट आरोप करने का कोई
प्रस्ताव नहीं है।
Facility of Post-mortem

* 120. Shri Kali Ram : Will the Health Minister be pleased to state—

whether there is a provision of any room for post-mortem in Government Hospital, Sahidnagar, if so, the reason for not doing post-mortem in the above said hospital?

शिक्षा नर्तकी (भीमदेवी गीता भुवनेश्वर मातरमेल) : हां, भीमदेवी गीता, भारतीय अस्पताल, सहिनाद ने पोस्टमॉर्टम के लिए एक कमरा उपलब्ध रखा है। अस्पताल में अब पोस्टमॉर्टम का शर्म शरीर की धरण ड्रेज करी नहीं गई है।

Posting of Principal in I.T.I., Kalka at Bhiwana

* 115. Shri Pradeep Chaudhry : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the post of Principal in IIT Kalka at Bhiwana is lying vacant; if so, the time by which this post is likely to be filled up;

(b) whether the posts of Group Instructor and instructors in IIT Kalka are lying vacant; if so, the time by which these posts are likely to be filled up; and

(c) whether the Heavy Vehicle Motor Mechanic course is being run in IIT Kalka; if so, whether any practical training is also being imparted to the students of this course?

श्री कृष्ण शिबर दुर्गा : 

(क) हां, भीमदेवी गीता, भौतिक प्रक्रियाओं संस्थान, तीव्राकार एंटरप्राइज में प्रवेशार्थी का वर्ष 1980 से रिक्त रहा है। तथापि, राज्य बिलोरा 8.3.2010 अदबुदार भी राज्य कुर्नार की नियुक्ति प्रवेशार्थी आईडीआईआई चालक के पद पर कर दी गई है।

(ख) हां, भीमदेवी गीता, वर्ग अनुदेशक के 3 पद तथा व्यवसाय अनुदेशक के 30 पदों में से 2 पद वर्ग अनुदेशक तथा 16 पद व्यवसाय अनुदेशक के पदों में से आखिरी दो पदों की शीर्ष ही नहीं जमीना सम्भावित है।

(ग) वैज्ञानिक विशेषज्ञ एनडी एमेट्रीज ऑफ़ इंडी रेडियो व्यवसाय भौतिक प्रक्रियाओं संस्थान कार्यालय में अब रहा है। इस व्यवसाय के कर्मचारी की भविष्यवाणी भौतिक प्रक्रियाओं संस्थान ने ही दिया जा रहा है। वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रबंध भौतिक प्रक्रियाओं परिवहन कार्यालय, बिलोरा में भी किया गया है, जब तक संस्थान में इस व्यवसाय की पूरी महमदाति उपलब्ध नहीं हो जाती।
Construction of New Road

श्री चरणजीत सिंह : नि:श:ति "शिरेवली निर्माण क्षेत्र में नव 2005-2009 के दौरान निर्माण नए सड़कों के निर्माण का आवेदन कर रहे हैं। उनके निर्माण का कुल राशि अबतिर हुई।"

<table>
<thead>
<tr>
<th>संरक्ष</th>
<th>सड़क का नाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>तालामोहना से तालामोहना कालोदा-रेडी लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>लोक निर्माण विभाग सड़क से गुलाबगरा बड़गुड़ा लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>बिराम से मलकड़ी पुल तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>बड़गुड़ा से धवन-भोग लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>भीम नदी से रोहन तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>पदराम से पकेरिहांग तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>बीलाना गुड़ड़ा से धुआसेका तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>दादू से सख्तान तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>दादू से कमल तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>तालामोहना से कुलुआना छोटे पुल तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>अलापगड़ से घुड़सवाना</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>लफल से कोरिसाना पंचायत सीमा तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>गुड़ड़ा से सादवलास-1 तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>रेडी में अन्नाद मंदिर की सड़क को जोड़ना</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>नाला चेज़ा से पावदाता तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>गर्वधाम चक्कों से दरदी तक लिंक सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>गुड़ड़ा से साड़र वर्क जंगली की सड़क</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>गंगाजल बनाली लोमड़ा</td>
</tr>
</tbody>
</table>

इन सड़कों के निर्माण पर 314.63 लाख रुपये की कुल राशि खर्च हुई।
Occupy of the Leasehold Houses and Plots

* 149. Smt. Kavita Jain: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give ownership by making registries in favour of these occupants of the plots of shops and houses given to them on lease by the Municipal Council, Sonipat; and

(b) if so, the time by which the registries are likely to be started together with the rate at which the said registries will be executed; and if not, the reasons thereof?

Vijaijyanti (Shri Mohan Pratap Singh):

(w) Yadi pochonwari ko aatad bhumi / bhuma aar durnatho ko naktik kahitya 600/- rupees ka samvad hae oor vah samvatini lathne samvad se unke karthe mere hae to tarakari te juk bharne mee niit hae.

(xi) Nagarpalika sonin wade te isam prakar ki samvatini ko sarejna ke liye ek pratyak prapti kahitya hae. Uske niit ko anugraha vichara jaaye ka.

To Segregate the load of Domestic Agricultural Sectors

* 5. Shri Ram Pal Majra: Will the Prime Minister be pleased to state whether there is any scheme to segregate the load of domestic sector and agricultural sector for the distribution of electricity in the State; if so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented together with the circlewise details thereof?

Vijaijyanti (Shri Mohan Pratap Singh), La Shriom, rajata m karne durnatho patra bhumipalika vah karthe rok kah karne ki ek yojana samvad ki jai. Sathivam samvad ke patra par pratnuli hae.

विवरण
संक्लायित नए दीवारों का विवरण निम्न प्रकार है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>स्थान का नाम</th>
<th>स्थापित किए</th>
<th>जलान करने का वक़्त</th>
<th>पूरा होने की संख्या</th>
<th>पूरा होने की अनुमानित तिथि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>उर्ध्वाधिकारिणी</td>
<td>63</td>
<td>63</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>अमुनानपर</td>
<td>84</td>
<td>84</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>पुरुषोत्तम</td>
<td>87</td>
<td>87</td>
<td>--</td>
<td>--</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Shifting of Indian Oil Depot

4. Shri Anil Vij: Will the Food & Supplies Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Indian Oil depots out of the town which are situated on G.T. Road, Ambala Cantt. in thickly populated locality; and

(b) if so, the time by which aforesaid depots are likely to be shifted?

विज्ञापन में (क्री नहादेश प्रवाम चिह्न) :

(क) ही अभियान चाही?

(ख) समय पर उत्कीर्ति वता पाना समय नहीं है।
Level of New Urlana Minor

* 21. Shri Krishan Lal Pauwar: Will the Irrigation Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that water does not reach upto village Kuran in situ on the tail of new Urlana Minor, District Panipat emanating from the Bitana canal; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to level the new Urlana minor; if so, the time by which the said minor is likely to be levelled?

कमल भंजी (केंद्रीय अर्थव्यवस्था कार्यालय):

(इ) नहीं श्रीमान जी, जब बुटाना बांड नगर में पर्यावरण प्लांट की उम्मीद है तब जिसका संबंध है कि नई उरलना माइनर के अन्तिम घाट पर लिखा है, तब यह नहीं पहुंचता है?

(उ) नहीं श्रीमान जी?

Illegal Buses and Vehicles

* 50. Smt. Kiran Choudhary: Will the Transport Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to check plying of illegal buses and vehicles in the state; and

(b) if so, the action taken against the defaulters?

राजदेव भंजी (र्री जोड़ प्रकाश जीना):

(इ) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 और नियम के अन्तर्गत कुछ वाहनों के संबंधित नियमित रेखांकन/संचालन की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पहली बार तार्किक आरोप फिरो बनाया है। इसके लिए किसी तरह के अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है?

(उ) लोकनायक के विश्वास नियमनसूची कार्यालय की जाती है। वर्ष 2009-10 (अप्रैल 2009 से जनवरी 2010) के दौरान निविदा प्रकाश के 29164 कारों का चालन किया और इन कारों के संबंधित (सूची में 33.29 करोड़ रुपए प्रदान किया)
Land transferred by HSIIDC to Reliance

84. Sh. Ajay Singh Chautala, Sh. Krishan Pal Gurjar,

} : Will the Industries Minister be pleased to state:

(a) how much land has been transferred by HSIIDC to Reliance Haryana SEZ and how much land has been purchased by Reliance for setting up the said SEZ/SEZs in Haryana;

(b) at what cost did the HSIIDC transfer the acquired land to Reliance for setting up the SEZ and at what price did Reliance buy the land for the said purpose directly from the farmers; and

(c) how much employment was required to be generated in the sanctioned SEZs and how much employment has actually been provided particularly for those belonging to Haryana?

विषयी मंत्री (स्थानीय प्रशन प्रवक्ता) : कृपया नाम जी. उत्तर लदन के प्रदेश पर रखा गया है।

(9) मैं निर्माण विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड, को हरियाणा राज्य विभाग विलयन (एप्लीकेशन फाइल) द्वारा 1365.86 एकड़ भूमि स्थानाधिकार की गई है। मैं निर्माण विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड ने भी 8202 एकड़ भूमि, जूनियर मालिका / किसानों से प्राप्त की है। विभाग से 1201 एकड़ भूमि के लिए रु. 700.01 रु. प्रति एकड़ की रेट में है।

(10) हरियाणा राज्य विभाग विलयन विभाग ने अवशेष भूमि विलयन हरियाणा एप्लीकेशन फाइल को विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड को विलयन करने के लिए 26.80 एकड़ प्रति एकड़ की दर से स्थानाधिकार की है। वस्तुनिष्ठ राज्य के आदिवासी हरियाणा राज्य विभाग विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना में 10 प्रतिशत मौजूदा भूमि मिलेगी। जूनियर मालिका को तीस हजार रु. प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से फुंडफ्लो (Annuity) की जाएगी और ऊपर 8.33 फेरदी रु. 800 मालिकाओं को अदा किए जा सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त विलयन हरियाणा विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड के लिए भूमि रु. 2200.00 प्रति एकड़ की दर से प्रदान की जाएगी।

(11) विलयन विभाग के अनुसार जब विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड, कामयाब होगा, उसमें कम से कम 4 लाख व्यक्तियों को वोटिंग विशेष (2 लाख अधिक के और 2 लाख अभी रोजगार)। इस परियोजना के बाद में विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में भूमि विलयन विभाग आईडी आईजी डी प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में 400 व्यक्तियों को वोटिंग विशेष देना होगा, जिनमें से 310 व्यक्तियों हरियाणा से आते हैं।
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

11.00 बजे  Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule 50.

PWD (ब&र) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move.

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

Mr. Speaker : Motion moved -

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

Mr. Speaker : Question is -

“That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 11th March, 2010.”

The motion was carried.

बिन्दुं दिखाओ का उदाहरण जाना / बांक आउट

श्री समाप्त मात्रा: अध्यक्ष नहोस, ये एक इमोडेट नॉन ऑफिशियल टैक्सीडूर्य दिया है कि साक्षात्कार विवाद के लिए केवल वर्षा और इन पूर्व के सिलसिले के पावनी जानी चाहिए क्योंकि प्रदेश में पावनी की रोटी है। अध्यक्ष गोलीम='', ये तो एक व्यापारी ने उनके केस को सुनीत सिटी में मामला उठाया है और अन्य एक व्यक्ति ने हिंदू नीति नेतृत्व के हो जाते है। (श्री एवं व्यक्ति)

Mr. Speaker : Majra Sahab, please listen. Please take your seat.

मुखर्मेंटी (श्री सुमेंद्र सिंह त्रुदा) : अध्यक्ष गोलीम, ये हाल को और हिरासत के लोगों को युगल दर रहें। (विनेता)

श्री समाप्त मात्रा: अध्यक्ष गोलीम, ये अपने मात्रा में सरकार दो सिलसिले करना चाहता हूं कि कल पावनी मान्यता लें इससे जोन ऑफिशियल दे को नॉन ऑफिशियल हो रहे। (श्री एवं व्यक्ति)

Mr. Speaker : Majra Sahab, Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरचेवाला: अध्यक्ष गोलीम, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात कहना चाहता हूं। नीति प्रावधान वीडियो की बात नौव्यु है। ये मुखर्मेंटी रहे हैं और रणदीप सिंह जी भी मात्राईमेंटी अध्यक्ष थे मिनिस्टर दे रहे हैं। ये आप जोन ऑफिशियल दे की दुकाई दे रहे हैं जबकि उन्होंने
Mr. Speaker: Majra Sahab, would you please sit down? (Interruptions)

Mr. Speaker: This is not relevant. (Interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, how he can intervene like this. (Interruptions) The Finance Minister is waiting for presenting the Budget and in between he is making running commentary. He should not be permitted to behave like this. (Interruptions)
Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2010-2011.

I rise with a sense of pride and humility to present the Budget Estimates for the financial year 2010-11 before this august House. I stand with a sense of pride because our Government in its previous tenure performed exceptionally well on all fronts of development. The people of Haryana have appreciated this performance and, in a historic verdict, have returned our Government to power for another tenure. I stand in all humility in view of the tremendous faith our citizens have reposed in our Government. Sir, through this august House, I wish to assure the people of Haryana that this Government will totally dedicate itself to working for their welfare.

2. The world witnessed a severe economic recession in the previous year, which bordered on the worst economic depression the world has seen in recent past. Many financial and corporate bodies were driven to the brink of bankruptcy and millions of people were rendered jobless and homeless. Major economies were seriously threatened. Our country, in fact, is amongst the few nations less affected by the economic slow down. The credit for this goes to the robustness and self dependence
of the Indian Economy, as well as the strategic reforms and corrective measures taken in the recent past by the Government of India, under the competent leadership of Dr. Manmohan Singh. There is no doubt, Hon’ble Speaker Sir, that the world will take a long time to recover fully from this crisis. However, clear signs have now appeared that for our National and State economies, the worst may be over and the proverbial light is visible at the end of the tunnel. I am optimistic that the concerted efforts of our Government, with the support of the private sector and the people of Haryana, will be able to bring Haryana back on the path of growth and prosperity.

3. Sir, in times of severe economic recession, Government spending is one of the major tools for arresting downturn. In the wake of the recession, the revenue receipts of the State were adversely affected. There was a significant decline in the growth rate of State tax revenues and collections under Stamp & Registration and Urban Development. Moreover, for the welfare of its employees, the State has fully implemented the pay revision package, which has cast a burden of over Rs.4000 crore during the current year. Despite these strains, the Government has not shied away from its responsibilities, and has actually increased the outlay for Annual Plan 2009-10 from the budgeted figure of Rs. 10,000 crore to Rs. 10,400 crore in the Revised Estimates, which is 46.31% higher than the actual plan expenditure in 2008-09. This reflects the deep commitment of our Government to fight the economic recession with all measures at its disposal and to maintain the pace of development in the State.

4. Our National and State economies are now showing signs of resurgence from the depression. Our country is poised to achieve a growth of over 7% in its G.D.P. in the current year. In fact, the performance of the UPA Government at the Centre, under the visionary guidance of Chairperson Smt. Sonia Gandhi, is so remarkable that in the World Economic Forum, recently held in Switzerland, experts projected that India is likely to emerge as the fastest growing economy in the world in 4 to 5 years. The State tax revenue receipts are also improving and the VAT collections during the latter half of this financial year reflect very positive trends. Therefore, Speaker Sir, I am optimistic that Haryana is now emerging from the clutches of economic recession and our Government shall strive hard to take it further on the path of growth.

STATE ECONOMY

5. During the financial year 2008-09, the State economy witnessed a very healthy growth of 18.4% in the Gross State Domestic Product (GSDP) over the previous year at current prices. At constant prices, with base year 1999-2000, the growth in GSDP in 2008-09 is 7.9%. The Primary sector contribution to GSDP stands at 19.8% in 2008-09, whereas that from the Secondary and Tertiary Sectors stands respectively at 28.8% and 51.4%. The sectoral analysis reveals that, at constant (1999-2000) prices, the contribution of the Primary Sector to Gross Domestic Product has registered an increase of 3.5 percent, while that of the Secondary Sector increased by 5.4 percent, and that of the Tertiary Sector recorded a growth of 11.2 percent. The declining share of the Primary Sector in GSDP, and the increasing share
of the Secondary as well as Tertiary Sector indicate a maturing of our economy, and its growth in the right direction. As per advance estimates, the GSDP at current prices for 2009-10 is likely to grow by 14.7%, while at constant (1999-2000) prices, the expected growth is 8.1%.

6. The per capita income of Haryana at current prices increased by 16.8% from Rs. 59,008 in 2007-08, to Rs. 68,914 in 2008-09. At constant prices, it increased by 6.2% from Rs. 39,462 in 2007-08 to Rs. 41,896 in 2008-09. During the current year, it is likely to grow further by 13% to Rs. 77,878 at current prices, and by 6.2% to Rs. 44,493 at constant prices. Haryana has the second highest per capita income amongst the States in India, being second only to Goa.

7. It is a matter of great pride for all Haryanavis that Haryana has the highest per capita income among the major States in the country. However, our State has suffered a disadvantage on this account in the report of the Thirteenth Finance Commission (TFC). The TFC has used the per capita income of Haryana as the yardstick to measure a criteria called “Fiscal Capacity Distance”, in its formula for horizontal distribution of central taxes amongst States. This criteria has been assigned the maximum weight of 47.5%, while the other criteria namely, population, area and fiscal discipline have been assigned weights of 25%, 10% and 17.5% respectively.

Thus, due to this unique position, the share of Haryana in shareable pool of Central taxes has marginally come down from 1.075% to 1.048%. However, the total devolution to Haryana under the 13th Finance Commission’s recommendations are Rs. 19,470.30 crore as compared to devolutions of Rs. 8,040.44 crore during the 12th Finance Commission period. I congratulate the Union Government on increasing the size of the divisible pool of the Central taxes from 30.5% to 32%.

NEW INITIATIVES

8. It is estimated that, in order to sustain a growth of 8 to 9 percent in the national economy, an investment of nearly Rs. 23 lakh crore is required on improvement of infrastructure during the 11th Five Year Plan. Investments of a similar order of magnitude would naturally be required in the State. You would agree, Sir, that this magnitude of investment is not feasible from the budgetary sources of the Government alone.

Our Government is, therefore, keen on involving the Voluntary, Non Government and Private sectors in our development process. We believe the participatory mode of development to be the best for our State and our society, and this is reflected sharply in our new initiatives which I will now outline before this august Assembly.

Policy for Non Government Organizations and Voluntary Sector

9. Our Government recognizes that the Voluntary and NGO sectors can work as effective instruments of inclusive development, by helping with proper identification of beneficiaries, reduction of delivery costs, flexibility and simplicity of approach and greater community participation in formulation of new schemes. As a logical extension of Decentralized Planning, we propose to formulate a policy for engaging the Voluntary and NGO sectors as development partners for the State.
policy would provide a framework for assisting such organizations through three instruments of partnership, namely, Consultation - through a formal process at the District and State level; Strategic Collaboration - to tackle complex interventions; and Project Funding. The project administration would be on the decentralized pattern recommended by the Planning Commission in the National Policy on the Voluntary Sector, and Mother NGO’s will be involved to select, train, fund and concurrently monitor field projects being implemented by field NGO’s on behalf of the Administrative Departments. This would bring in greater responsibility, transparency and accountability to our social sector projects.

Policy for Public Private Partnership Projects

10. In the complex current economic scenario, adequate development of social and physical infrastructure, which are pre-requisites for sustainable economic growth, can only come from pooling of all available resources - from government, non-government as well as private sectors. Therefore, the Public Private Partnership (PPP) mode of development assumes great significance. We propose to formulate a comprehensive policy on PPP projects in order to create an enabling environment in the State for facilitating private sector participation in improvement of the physical and social infrastructure. We intend to extend the PPP approach even to niche areas such as providing tertiary level health care at affordable cost to our population.

Haryana Infrastructure Development Board

11. Providing a framework for fast track implementation of the PPP projects is necessary to fully reap the benefits of the major investments we hope to initiate through the policy on PPP. We propose to do so by setting up Haryana Infrastructure Development Board, which would act as a nodal agency for conceptualization, financing, implementation, maintenance and operation of PPP projects in the State and also as a special purpose vehicle to take up major infrastructure projects funded out of State resources and other levies and charges.

East-West and North-South Expressway Corridors

12. Sir, our Government has the grand vision to spread the benefits of economic development to the remotest corners of Haryana. We propose to open up the hinterland by providing easy access by building an East West and a North South expressway corridor through the State. The project, likely to cost around Rs.2,000 crores, will be in the PPP mode with a mixed model of BOT(Toll) and BOT(Amortity). The interior areas along the corridors will open up for industrial, commercial, estate development and allied activities, thereby creating enormous opportunities for growth and employment.

Haryana Metro

13. The proximity to Delhi is a unique advantage for Haryana, and our State territories constitute a large part of the National Capital Region. To fully exploit this advantage, we intend to set up Metro rail links connecting our bordering cities with Delhi. The 7.05 km long Gurgaon Delhi Metro link is nearing completion. We propose
to extend this to Manesar and also provide a high-speed link to the Indira Gandhi International airport. Sikanderpur station is going to be connected via a 100% private Metro link to Noida by M/s Rapid Metro Rail, Gurgaon Ltd. Delhi Metro is to be extended to Faridabad through a 13.87 km link. The project for linking Bahadurgarh to the Mundka border of Delhi is under process. At present, the various metro projects of Haryana are being implemented by the Delhi Metro Rail Corporation, which is a joint venture company of the Government of Delhi and the Government of India. For speedy and efficient implementation of our Metro projects, we propose to set up a joint venture company with the Government of Haryana holding a majority equity share, as has been done by the States of Karnataka and Tamil Nadu.

**Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana**

14. The population of our cities has been steadily increasing, and there is a growing need for holistic development of the urban areas with focus on improvement in infrastructure, efficient service delivery mechanisms, community participation and transparency. The Government proposes to launch the *Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana (RGUDMH)*, a state-wide urban infrastructure development program, in all cities of the State excluding those covered under Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission. RGUDMH will be funded from the budgetary allocations as well as contributions from the Fund for Development of Major Infrastructure Projects, and will catalyze further investments under PPP mode. I propose to earmark Rs. 2500 crore for RGUDMH over the next five years, beginning with a sum of Rs. 500 crore during 2010-11. RGUDMH will focus on the following components: affordable housing for the urban poor, including social and rental housing; in situ slum development in conjunction with the *Rajiv Awas Yojna* of the Government of India; Water Supply, Storm Water Drainage and Sewerage; integrated Solid Waste Management; and other civic amenities. For 2010-11, RGUDMH will broadly spend Rs. 200 crore on projects for water supply and sanitation, Rs. 100 crore on affordable housing projects, and the remaining funds will be used for special purpose infrastructure development projects in small and medium towns. The nodal agency for implementation of Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana shall be Haryana Urban Infrastructure Development Board which would now be headed by the Hon’ble Chief Minister. There will be a State Level Committee headed by the Chief Secretary for identifying and recommending the projects and overseeing their execution.

**Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme**

15. Our Government firmly believes that every human being has the right to a dignified old age and has significantly enhanced the old age pension. However, a large section of our working rural and urban population, particularly those working in the informal or unorganized sectors, is vulnerable to old age poverty. We propose to initiate the *Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme* for the members of milk cooperatives and cane growers’ cooperatives, wherein each member will contribute Rs. 200 per month, the Society/Federation/State Government will co-
contribute Rs.100 per month, and the Government of India will co-contribute Rs. 1000 per annum. The contributions will go to a fund managed professionally as per the guidelines of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. The fund will provide the worker with a retirement pension to support him in his old age.

Economic Stimulus Package

16. Hon'ble Members would recall that my predecessor had introduced an Economic Stimulus Package in the last budget to help fight the recessionary trends of the economy. Various works have been initiated under this package, such as upgradation of district hospitals, setting up of new medical colleges, improvement of water supply and sanitation facilities in urban areas, setting up of special care institutions for the disadvantaged sections of the society, restoration of water courses, housing for the industrial workers and construction of office and residential buildings for the new districts of Mewat and Palwal. Rs.332.56 crore have been released under the stimulus package so far, and I have made an allocation of Rs.713.79 crore for the works under the Stimulus Package for 2010-11.

17. Sir, before I take up sector-wise allocations, let me just highlight a few facts which will put the efforts of our Government in the right perspective. The total plan expenditure during the five years from 2000 to 2005 was only Rs.9,235.41 crore, whereas the plan expenditure for just the current year is going to cross Rs.10,400 crore! In the last five years, our Government spending on the State Plan was 230.13% higher than that of the previous regime. The average annual plan outlay growth rate during 2005-2010 is 37.83% per year, compared to just 4.8% during 2000-2005! This has been made possible by the strong commitment of our Government to development of the State.

POWER

18. Universal availability of quality power is critical for the economic development of the State, as well as for the comfort of its citizens. Our Government has accorded the highest priority to this sector and we are committed not only to adding adequate generation capacity to achieve the target of making Haryana a power surplus State, but also to upgrading our transmission and distribution systems for maximum efficiency and reliability. Due to the efforts of our Government, Hon'ble Speaker Sir, the average power availability per day in the State, which was only 578 lakh units in 2004-05, has gone up to 907 lakh units in the current year!

19. Tremendous progress is being made in enhancing the power generation capacity of the State. I would like to inform the Hon'ble Members that, in the period from 1999 to 2005, only 704.4 MW was added to the own generation capacity of Haryana, whereas, during the first tenure of our Government from 2005 to 2010, we have already added 1117.8 MW. The first 600 MW Unit of the 1200 MW Rajiv Gandhi Thermal Power Project at Khedari, Hisar has already been synchronized on 29.12.2009 and the second Unit will be ready for commissioning in April, 2010. This will be followed by the first 500 MW Unit of Indira Gandhi Super Thermal Power Station at Jhajjar, in July, 2010 and subsequently the second & third 500 MW Units
in December, 2010 and February, 2011 respectively. The first 660 MW Unit of Mahatma Gandhi Super Thermal Power Project at Jhajjar is targeted to be commissioned during December, 2011 and another 660 MW Unit-II will start generating power by May, 2012. For the 2800 MW Nuclear Power Plant to be set up at village Gorakhpur in district Fatehabad, pre-project work has been started by the Nuclear Power Corporation of India Limited for setting up two Units of 700 MW each in the first phase. Sir, you would agree that we are well on our way to double the availability of power in the State by 2011-12.

20. For up-gradation of the transmission network in the State, Rs. 3,365.8 crore are being spent to add 25 substations of 66KV and above in 2009-10, and 72 substations in 2010-11. The first 400KV substation of the State has been set up at Kori. We plan to augment our transformation capacity by 5000 MVA during the 11th Plan.

21. Our effort, Sir, is to provide quality power to all citizens. Segregation of the rural domestic and agricultural loads and introduction of High Voltage Distribution System are important steps to improve the quality and efficiency of power supply in the rural areas. Under the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna, 91,347 connections have so far been released to families below poverty line (BPL) this year.

22. I am allocating Rs. 4,642.71 crore for this sector during 2010-11 which is 20.66% higher than the allocation for the current year. This includes Rs. 1,670.67 crore on Plan side and Rs. 2,972.04 crore on Non-Plan side.

WATER SUPPLY AND SANITATION

23. Sir, a milestone was achieved in 1992, when drinking water supply facilities were extended to all the villages in the State. However, the approved norm of 40 liters per capita per day (lpcd) could not be achieved in some villages. A comprehensive survey in December, 2004 identified 1971 such villages. Our Government has accorded high priority to augmentation of water supply in these deficit villages, and I am proud to state that water supply in all 1971 deficient villages would stand augmented as per the approved norm by 31st March, 2010. In addition, augmentation of the water supply is being carried out in 950 villages under various schemes during this year.

24. The Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Augmentation Project in Mewat will be completed by March 31, 2010, covering 503 villages at a cost of Rs. 205.91 crore. Further augmentation of water supply from 55 lpcd to 70 lpcd in all these villages, with an outlay of Rs. 94.58 crore, will commence in 2010-11. Under the Indira Gandhi Drinking Water Scheme, private water connections have been provided to 7.83 lakh Scheduled Caste households.

25. Adequate attention is also being given to improving the water supply and sanitation facilities in the urban areas. Our Government has waived the sewer connection charges for a period of one year from November, 2009 in order to encourage
the improvement of sanitary conditions in towns. Second water works based on canal water filtration have been commissioned in Rohtak and Dadri, and sewage treatment plants have been commissioned in Kaithal and Jind, while those in Rohtak, Hodal and Narwana are near completion.

26. In the National Capital Region, water supply projects for 10 towns and sewage system projects for 8 towns are under implementation with support from the NCR Planning Board. This year, sewage system projects in Sonepat and Gohana, and a water supply project in Sonepat have been approved.

27. Under the Economic Stimulus Package, 15 towns have been selected, namely, Ambala City, Bhawan, Charkhi Dadri, Fatehabad, Hansi, Jullana, Kalayat, Assandh, Karhal, Mahendergarh, Narnaul, Sirsa, Ellenabad, Tughla and Uchana for 100% coverage of Water Supply and Sewerage facilities. Phase-I of the project, amounting to Rs. 955.71 crore, has recently been approved by the Government.

28. I am allocating Rs. 1,297.69 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 669.48 crore on Plan side and Rs. 628.21 crore on Non-Plan side.

ROAD NETWORK AND PUBLIC WORKS

29. Sir, our Government is committed to improving the road network in the State. Up to 31.1.2010 during the current financial year, 3,903 Kms. length of roads has been improved at a cost of Rs. 1,476 crore under various schemes and projects. A length of approximately 4,100 Kms. will be widened/strengthened/reconstructed and improved in 2010-11. Under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, which is now a part of Bharat Nirman Scheme, 710 Kms. of rural road have already been improved during the current year at a cost of Rs. 239 crore. The PPP project for improvement of the Gurugram-Panipat and Ballabgarh-Sohna road has already been taken up on BOT (Toll) basis with a negative grant of Rs. 130.30 crore. The NCR Planning Board has sanctioned road projects worth Rs. 638 crore this year.

30. Steady progress has also been made in the construction of Road Over-bridges. 55 ROB's have been sanctioned by the Government, 16 ROB's have been opened to traffic, and 13 more are under construction. To provide further impetus to road infrastructure development, the 2nd phase of the Rajiv Gandhi Bridges & Road Infrastructure Program has been taken up with an increased outlay of Rs. 5000 crore. Work is going on for completion of 75 km length of Rohtak-Jhajjar-Rewari Railway line and 88 km long Sonepat-Jind Railway line. These works, costing Rs. 596 crore, are under execution on 50:50 sharing basis with Indian Railways.

31. During this year, 114 public buildings have been completed at an approximate cost of Rs. 215 crore. Work is going on in 700 building works having an approximate cost of Rs. 1500 crore. Special attention is being given to maintenance and upkeep of public assets.

32. I am allocating Rs. 1,938.95 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 1,311.97 crore on Plan side and Rs. 626.98 crore on Non-Plan side.
IRRIGATION

33. Speaker Sir, the Department of Irrigation will be completing a number of important projects during the coming financial year. The 70 km long NCR Water Supply Channel for carrying drinking water supply to Gurgaon, Manesar, Bahadurgarh, Sampla and Badli will be completed by June 2010 at a cost of Rs.322 crore. Kaushalya Dam on the Ghaggar River in Panchkula district will be completed at a cost of Rs. 180 crore. Carrier Lined Channel for the supply of drinking water to Delhi, and the second phase of Shahabad-Dadupur-Nalvi Project will also be completed in the ensuing year. The capacity of Western Yamuna Canal Main Line Lower has been increased from 13,300 cusecs to 19,557 cusecs. Recharge channel for Massaul Barrage, deepening of Ottu Lake and Bhindawas Lake are the other projects under implementation. To alleviate the problem of water scarcity in the backward area of Mewat, a detailed project report is under preparation for construction of the Mewat Canal.

34. Water is an important resource, and we are a water deficit State. The present irrigation water requirement of the State is around 36 million acre feet (MAF), whereas the surface and ground-water availability is merely 14 MAF. The deficient monsoons in the current year and lower levels in the Bhakra Dam and Pong Dam reservoirs did aggravate the problem of low water availability for our State. Our focus, therefore, has to be on saving water losses by all means, and ensuring optimal and equitable deployment of available water resources. During the next year, we propose to undertake construction of 500 new lined water courses and rehabilitation and remodeling of more than 500 minor and distributaries in the State, many of which were constructed more than 20 years ago.

35. I am allocating Rs.1,616.49 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 768.17 crore on Plan side and Rs. 848.32 crore on Non-Plan side.

INDUSTRIES AND COMMERCE

36. Haryana has emerged as a favoured investment destination in northern India for industry, and scores amongst the top States in India on per capita investment performance. Provision of quality infrastructure following the Industrial Model Township (IMT) approach has been a key factor in this performance. Our future plans include expansion of IMT, Manesar, development of an IMT near Rohtak, Phase-II of IMT Rohtak, Phase-IV of Growth Centre Bawal, Manakpur, Barhi and Panipat are under process. Establishment of an IMT in district Ambala is also under consideration. The HSIIDC proposes to invest over Rs. 1,200 crore on land acquisition and development of industrial infrastructure during the ensuing year.

37. Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project (DMIC) is being developed along the alignment of the Delhi-Mumbai freight corridor. A Multimodal Logistic Hub, an Exhibition-cum-convention Centre and a Mass Rapid Transport system from Gurgaon to Bawal have been identified as the early bird projects under this mega
project. Under the Economic stimulus Package, special dispensation is being made for creation of housing stock for industrial workers.

38. To equip our own people to reap the advantage of industrialization, our Government is establishing a number of skill development facilities. These include the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Footwear Development and Design Institute at IMT Rohtak, Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET) at Murthal, and Indian Institute of Corporate Affairs at IMT Manesar. I am confident that the various steps taken by the Government for development of infrastructure, improved power availability and congenial labour relations, along with a new Industrial Policy, would take the State to new investment horizons.

39. I am allocating Rs.164.06 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 125.61 crore on Plan side and Rs.38.45 crore on Non-Plan side.

INFORMATION TECHNOLOGY AND e-GOVERNANCE

40. Alongside the overall industrial investment, Haryana has emerged as a preferred investment destination for the IT Industry as well. Out of a total of 46 SEZ’s that have been formally approved for the State of Haryana, 35 are in the IT Sector. In addition, the State has granted licences to 27 proposals for the establishment of IT/Cyber Parks. Software exports from Haryana have exceeded Rs.21,000 crore during 2008-09.

41. Our State is among the leaders in the establishment of Information Technology infrastructure under the National e-Governance Plan. The State Wide Area Network has already been set up. The State Data Centre is going to be established in the ensuing year. We are taking concrete steps to leverage the use of information and communication technology in governance. Major e-Governance projects are under implementation in the Food and Supplies Department, Transport Department, Commercial Taxes Department and Treasuries. We propose to create a cadre of IT professionals in the State for smooth implementation and sustenance of e-Governance initiatives in the State.

42. I am allocating Rs.19.59 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 19.35 crore on Plan side and Rs.0.24 crore on Non-Plan side. There will be substantial additional investment by the line departments on their individual e-Governance initiatives.

TRANSPORT

43. The vision of our Government is to make Haryana a model State with fast, equitable and inclusive development. Therefore, we lay as much emphasis on improving citizen services across the State as we do on creation and up-gradation of infrastructure for economic growth. In order to provide reliable, safe and efficient passenger transport services to each and every village in the State, a comprehensive passenger transport policy is being formulated. The policy aims at setting up a state-wide network of bus services, comprising both private service operators and
Haryana Roadways. To promote road safety in the State, Institutes of Driving Training and Traffic Research are being established in collaboration with auto majors such as Maruti Suzuki, Ashok Leyland and Tata Motors at Rohtak, Kaithal and Bahadurgarh.

44. To meet the needs of our citizens, our Government intends to increase the total fleet strength of Haryana Roadways to 4500 buses by the end of the 11th Plan period. Special attention is being paid to inter-city transportation and a City Bus Service is proposed to be setup under PPP mode in Gurgaon. The Faridabad-Gurgaon-Delhi bus service has recently been started under INNURM. We also propose to construct Multi-modal Hubs/ Modern Bus Stands under PPP mode at 20 locations in the State.

45. I am allocating Rs.1,142.10 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.92.72 crore on Plan side and Rs.1,049.38 crore on Non-Plan side.

AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS

46. Sir, this sector continues to be the mainstay of livelihood for a majority of our population. The great progress made by our State in this sector is reflected in our food grain production, which has increased six fold from 25.92 lakh tons at the inception of Haryana in 1966-67, to a record 161.66 lakh tons during 2008-09. The weak monsoons this year have led to a marginal reduction in the cultivated area under both Kharif and Rabi crops. However, due to the efforts of our farmers and the Government, there is no reduction in production and we are likely to achieve the target of production of 167.14 lakh tons during the current year.

47. The consumption of fertilizer has touched 14.35 lakh MT and is 11.24% higher than last year’s consumption. However, declining soil health is a matter of concern for us, and micronutrients play an important role in soil fertility. Hence, the Agriculture Department has prepared a new plan scheme for managing micronutrient deficiency, in which 50% subsidy will be provided for micronutrient fertilizers up to a maximum of Rs. 500/- per hectare with a ceiling of 2 hectares per farmer. Various other schemes for restoring soil health and increasing agricultural production will continue in the ensuing year.

48. Keeping in view the interest of the farmers, the State Government has fixed the basic cane price of early, mid & late maturing varieties of sugarcane at Rs.185/-, Rs.180/- and Rs.175/- per quintal, respectively, during the current crushing season which is the highest State Administered Price in the country. In addition, our cooperative sugar mills have given a bonus of Rs. 25 per quintal. The Shahabad, Karnal and Panipat sugar mills have further shared their profits with the farmers by giving an additional bonus of Rs.40, Rs.30 and Rs.20 per quintal respectively. To enhance sugarcane production in the State, a Technology Mission on Sugarcane is proposed by our Government for 2010-11. Moreover, the basic cane prices for early, mid and late varieties have been further enhanced respectively to Rs.210/-, 205/- and Rs.200/- per quintal for the crushing season of 2010-11. The bonus will be decided before the crushing season commences.
49. To protect our farmers from the vagaries of nature, a new insurance scheme called Weather Based Crop Insurance Scheme has been conceived to compensate yield loss due to adverse weather conditions. The scheme is being implemented on a pilot basis for wheat crop during Rabi season 2009-10 in Ambala II, Bubain and Tohana blocks.

50. Animal Husbandry and Dairying are an integral part of our agrarian economy, and the Government is fully conscious of its contribution to the prosperity of our farmers. A network of 2,789 Veterinary Institutions caters to the 90.93 lakh strong livestock population of the State. Efforts will be made to open 80 new Veterinary Institutions during 2010-11. One pet animal medical centre-cum-teaching hospital has been set up at Panchkula and super specialty poly clinics have been established at Sonipat and Bhiwani. Another such poly clinic is being setup at Sirsa. The Haryana Dairy Development Cooperative Federation is providing procurement, processing and marketing support to the 5100 dairy cooperatives in the State. Sir, you will be happy to know that farmers are being paid Rs.340 per kg fat for milk at present, whereas they were being paid a mere Rs. 165 per kg fat in 2005.

51. The cooperative movement has played a pivotal role in supporting the agriculture and allied sector in the State. Over 35 thousands Cooperative Societies of different types, having over 57 lakh members, are working in the State. The cooperative credit structure at the grass root level has been restructured by amalgamating 2,441 Primary Credit Cooperatives Societies into 620 Primary Agricultural Cooperative Societies. Under the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme of Government of India, loans worth Rs.830.73 Crore have been waived for 2,61,230 small and marginal farmers, while 2,00,734 other farmers have been provided a relief of Rs. 343.16 crore under the scheme.

52. In March 2009, our Government slashed the rate of interest on crop loans from 11% to 7%. The State Government is giving an interest relief of 2% on timely repayment of crop loans, while the Government of India is paying an interest relief of 1%. With these interest subventions, the effective rate of interest on crop loan is now just 4%. For long term non-agricultural loans, the State Government has increased interest subvention from 3% to 5% under the Timely Repayment Incentive Scheme, which has been extended up to 31-12-2010. Moreover, our Government has also modified the provision in the Haryana Cooperative Societies Act, 1984 under which cooperative loans were recovered as arrears of land revenue. Henceforth, no farmer in the State can now be arrested for recovery of cooperative loans. This, Hon'ble Speaker Sir, shows how deeply our Government respects the dignity of our farmers.

53. The State Government has set up the State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (State CAMPA) in accordance with the guidelines of the Government of India. This Fund will be utilized for the protection and management of natural forests and wildlife sanctuaries, compensatory afforestation, environmental services and research and development. Under the Forest (Conservation) Act, 1980, a contribution of Rs.187.43 crore has already been made to this fund by the User agencies against sanctioned proposals.
54. I am allocating Rs. 1,073.62 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.540.66 crore on Plan side and Rs.532.96 crore on Non-Plan side.

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS

55. Our Government will continue its focus on the development of the rural areas. A number of schemes are being implemented, both in the Central and State sectors, for upgradation of rural infrastructure, employment generation and alleviation of poverty as well as other pressing issues. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, a sum of Rs.78.49 crore has been utilized up to the end of January, 2010 for generating 39.68 lakh person-days of employment in the rural areas of the State. Assistance of Rs.18.40 crore has been provided to 11,851 swarozgars under the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana. To further promote self-employment, Rural Development and Self-employment Training Institutes are being set up in existing IIT campuses in five districts. Under the Indira Awaas Yojana (IAY) Scheme, 13,604 houses have been constructed and 6,309 houses are under construction in the current financial year. Backward Regions Grant Fund scheme is being implemented in Mahendgarh and Sirsa districts to bridge critical gaps in village infrastructure and facilities.

56. Our Government is providing free residential plots of 100 sq yard each to eligible Scheduled Caste, Backward Class (A) and Below Poverty Line families in planned and developed lots under the Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojna. Out of 6 lakh identified eligible families, 2.91 lakh families have been allotted plots in the first phase in villages where panchayat land was available. The remaining villages will be covered in the second phase. Villages having more than 50% SC population are being provided basic infrastructure under the Mukhya Mantri Amsuchit Jatiji Nirmal Basti Yojna. In the first phase, Rs.117.85 crore have been released for taking up 442 works in 391 villages. Mukhya Mantri Sanitation Incentive Puraskar Yojna has been launched to provide incentive to panchayats for improving cleanliness and eradicating the practice of open defecation in the villages.

57. I am allocating Rs.956.17 crore for this sector during 2010-11 which is 7.09 % higher than the allocation for the current year. This includes Rs.613.54 crore on Plan side and Rs.342.63 crore on Non-Plan side.

URBAN DEVELOPMENT

58. Sir, I have already mentioned the great importance that our Government gives to the improvement of infrastructure and facilities in urban areas. The financial position of many of the urban local bodies is weak, and the economic slowdown has further affected their finances. In order to provide a steady source of income to our local self government entities, I propose to impose a small surcharge on VAT in the State. Out of the collections under the surcharge, 80% will be given to Urban Local Bodies and 20% will be given to Village Panchayats. This will help these local bodies take up new development projects in their areas on a sustained basis.

59. City Development Plans (CDP) of 73 towns have been prepared to map their basic infrastructure gaps and needs. Under the Jawaharlal Nehru Urban
Renewal Mission (JNNURM) of the Government of India, Rs.823.33 crore have been sanctioned for 7 projects for Municipal Corporation, Faridabad. Now Panchkula has also been included under JNNURM and its CDP is under consideration of the Government of India. Under the Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), new projects for Integrated Solid Waste Management at Rohtak, Karnal, Indri, Yamunanagar & Jagadari and projects for Sewerage System & Sewerage Treatment Plant at Babadurgarh Phase-I and II, Amhala Sadar, Narnaul and Charkhi Dadri have been sanctioned for Rs.164.07 crore. Under the Integrated Housing and Slum Development Program, 16,608 dwelling units are being constructed for slum dwellers.

60. To ease the mounting pressure on infrastructure in the mega cities like Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad, the Government of India has launched a centrally sponsored scheme called Urban Infrastructure Development in Satellite Towns. The scheme aims at developing satellite towns near the mega cities as counter magnets by upgrading urban infrastructure facilities such as transport, drinking water, sewerage, drainage and solid waste management. The Government of India will bear 80% of the cost of the scheme, while the balance will be equally shared by the State and the urban local body. The scheme will be implemented in Sonipat town for which a provision of Rs.100 crore is proposed for 2010-11.

61. I am allocating Rs.1,447.14 crore for this sector during 2010-11 which is 26.50% higher than the allocation for the current year. This includes Rs.1,324.83 crore on Plan side and Rs.122.31 crore on Non-Plan side.

SCHOOL AND HIGHER EDUCATION

62. Education is the cornerstone of development, and our insurance for the future of the State. Its critical importance and centrality to human resource development cannot be over-emphasized. Speaker Sir, this Government is committed to making education universally accessible and inclusive for all sections of the society. The Hon'ble Members would be happy to know that now, in Haryana, a primary school is available to a child within a radius of 1.03 km, a middle school within 1.07 km, a high school within 1.52 km and a senior secondary school within 2.28 km. This Government has upgraded 21 Middle Schools to High Schools and 53 High Schools to Senior Secondary Schools. Our seriousness in this sector can be gauged from the fact that the total budget of the education department, which was Rs.1,733.18 crore in 2004-05, has gone up to Rs.5,331.35 crore in Revised Estimates 2009-10.

63. We do realize that creation of infrastructure, though necessary, is by no means sufficient for quality education. A number of schemes are being run by the State and the Centre to attract children to schools and to retain them. These include the Mid-day Meal Scheme, the Rajiv Gandhi Scholarship Scheme and other scholarship schemes, Monthly Incentive Schemes, Cash Awards Scheme and others. The Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), implemented in financial partnership with the Central Government, has been instrumental in improving the quality of elementary education by provision of teachers, opening of schools and alternate school facilities,
quality improvement programs and creation and improvement of infrastructure. Following the success of SSA, with the intention of making quality secondary education available, accessible and affordable to all young persons in the age groups 14-16 years, the Government of India has launched the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. The RMSA is funded by the Centre and State Governments in the ratio of 75:25, and provides for various improvement schemes on the pattern of Sarv Shiksha Abhiyan.

64. To improve female literacy, the Saakshar Bharat Scheme of the Government of India has been launched in Karnal district this year. The scheme will subsequently be extended to 9 more districts having 50% or less adult female literacy, namely, Kaithal, Jind, Fatehabad, Hisar, Sirsa, Bhiwani, Gurgaon, Mahendergarh and Faridabad.

65. Higher Education has a different set of challenges and issues from School Education and is critical to qualitative social growth of the State. To ensure closer attention and a sharper focus on its development, our Government has created a separate administrative department of Higher Education. For expansion of outreach, one Central University at Mahendergarh and two private universities have already become operational. More private universities are at advanced stages of being set up. BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonepat will be further improved and strengthened. A number of schemes are also being implemented to enable children from weaker sections of the society to acquire higher education.

66. Teaching activity in schools gets disrupted every month with the retirement of teachers. In order to avoid such disruption, our Government has taken a historic decision to re-employ retiring teachers till the end of the academic session.

67. I am allocating Rs.5,946.29 crore for this sector during 2010-11 which is 11.53% higher than the allocation for the current year. This includes Rs.1,490.32 crore on Plan side and Rs.4,455.97 crore on Non-Plan side.

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

68. Quality technical and professional manpower is the most important resource for the socio-economic development of a State. At the time of its inception, Haryana had only 6 polytechnics and one engineering college in the State with a total annual intake of 1,341 students. Now, 1,12,910 students pass out every year from 346 institutions, including 141 engineering colleges.

69. The network of technical institutions is continuously growing. 6 new Government Polytechnics have become operational at Madalpur (Faridabad), Hathnikund Barrage (Yamunanagar), Meham (Rohtak), Basai (Gurgaon), Indri (Mewat) and Mandkola (Mewat). Seven more polytechnics are being opened in Rewari, Kaithal, Panchkula, Panipat, Fatehabad, Kurukshetra and Yamunanagar districts. The prestigious Indian Institute of Management (IIM) is to be set up in 213 acres of land at village Gharwanati in Rohtak.
70. To prepare our students for skilled industrial jobs, a network of 109 Government Industrial Training Institutes and 74 private Industrial Training Centers is operating in the State with an annual intake of 27,792 and 10,976 students, respectively. 26 New ITI's will be opened in the next three years, while 22 existing ITI's will be expanded. Besides, 29 ITI's and 1,500 skill development centers will be established in PPF mode in the State during the next five years.

71. I am allocating Rs.431.12 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs.300.11 crore on Plan side and Rs.131.01 crore on Non-Plan side.

HEALTH

72. One of the key functions of a democratic government is to provide reliable, affordable and accessible healthcare to its citizens. This Government is striving hard to improve the quality of health infrastructure, the availability and quality of doctors, availability of free medicines, and efficient delivery of health and medical services. The State is providing healthcare through 52 hospitals, 94 Community Health Centers, 441 Primary Health Centers, 2,465 Health Sub-centers, 20 District TB Hospitals and 51 Dispensaries. Free drug supply to all the patients and introducing the Surgery Package Program are among the major initiatives of the Health Department. Six district hospitals at Sirsa, Hisar, Bhiwani, Faridabad, Sonipat and Rohtak, are being upgraded into state-of-the-art Multi Specialty Hospitals with an expenditure of more than Rs.102 crore under the Economic Stimulus Package. Three district hospitals at Rewari, Panipat and Panchkula will be upgraded and Civil Hospital at Dauri will be expanded to 100 beds during 2010-11.

73. Construction of two medical colleges at Kharar Kalan (Sonipat) and Naiher (Mewat) has been started under the Economic Stimulus Package at an estimated cost of Rs. 617.61 crore. The Government has also announced setting up of Kalpana Chawla Medical College at Karnal. Pt. B.D. Sharma Post Graduate Institute of Medical Studies, Rohtak is to be upgraded to the level of All India Institute of Medical Studies under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna. For this purpose, a sum of Rs.125 crore has been earmarked by the Government of India and Rs.25 crore will be contributed by Haryana.

74. On 26 January, 2010, our Government launched the Nehru Bal Drishiti Yojana, a new scheme under which eye collection centers have been set up and linked to "102" services in each district. At present one Eye Bank exists in the State at PGIMS, Rohtak. We propose to set up another Eye Bank in the State in the ensuing year.

75. I am allocating Rs.1,125.48 crore for this sector during 2010-11 which is 6.07% higher than the allocation for the current year. This includes Rs.455.85 crore on Plan side and Rs.669.63 crore on Non-Plan side.

SOCIAL WELFARE

76. Haryana Government is fully committed to the welfare of the vulnerable sections of the society and has undertaken a series of effective steps to provide social
security to the aged, widows, destitute women, handicapped persons, eunuchs, dwarfs, persons from minority communities and families with only girl child/children. A provision of Rs.1,465.46 crore has been made for these schemes for the current year.

77. To ensure that citizens with disabilities are not left out of the mainstream of development, our Government has launched an ambitious Jawahar Social Infrastructure Mission to take up projects for this section of our society. Under JSIM, we propose to set up 10 schools for the visually challenged children, 8 schools for the children with hearing and speech impairments, 6 schools for the differently abled children, three State Level Institutes for providing vocational training to persons with different physical disabilities, 4 Senior Citizens' homes, 21 Vocational Training Centers and two Life Long Homes for the differently abled persons in the next three years at a cost of Rs.150 crore.

78. In order to encourage Scheduled Caste girl students to go for higher education, a new scheme namely Anusuchit Jati Chhatra Utch Shiksha Pratshaban Yojana has been launched for the year 2009-2010 wherein annual scholarships ranging from Rs.5000 to Rs.14000 are being provided to Scheduled Caste girl students studying science, commerce or professional courses. Dr. Ambedkar Medhavi Cabhatra Yojana has been extended to post graduate classes. The popular Ladli scheme for supporting the second girl child, initially launched for five years, has been extended for another five years.

79. I am allocating Rs.2,167.15 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 2,010.20 crore on Plan side and Rs.156.95 crore on Non-Plan side.

RECRUITMENT IN GOVERNMENT

80. In a democratic setup, the government is a vehicle for the delivery of development, infrastructure and social services to the citizens. Therefore, the efficiency of the government as an organization, as well as the bottlenecks in its operations, assumes importance. One of the main bottlenecks in government functioning at present is the delay and inconsistency in recruitment of human resource. We have, therefore, identified the services and cadres which need frequent recruitment to meet the requirements of different departments, public undertakings, boards and corporations, and decided that the Haryana Public Service Commission and the Haryana Staff Selection Commission will hold annual examinations, at pre-determined dates, for recruitment thereto, so that the candidates do not have to apply time and again. Accordingly, the HPSC will annually conduct the Engineering Services Combined Examination, Agriculture and Allied Services Combined Examination, and Legal and Allied Services Combined Examination, whereas the HSSC will conduct Graduate Level Combined Examination, Junior Engineers and Allied Services Combined Examination, Clerks Grade Examination, Drivers Combined Test and Steno-typists/Stenographers Combined Examination.

81. Basic minimum eligibility qualification in respect of similar category posts shall be uniform in all Departments, Boards, Corporations, Companies and Societies. There shall be a Uniform Application Form in computer readable format.
Self certified copies of certificates relating to caste, residency, age, physical handicap etc. will be accepted at the application stage. Original certificates shall be checked only at the time of interview and joining of selected candidates.

82. We have also decided that all fresh recruits will undergo mandatory induction training for 3 months after joining so that they are well prepared for their respective jobs. They will be given postings only after completing such induction training.

BUDGET ESTIMATES 2010-11

83. Sir, I would like to draw the attention of Hon’ble Members to the fact that the Budget Estimates I bring before this august House for voting this year are in a slightly modified form. You will notice, Sir, that this time we are proposing 43 Demands for Grants as against the traditional 25 Demands. Recognizing that the State expenditure pattern has undergone significant changes in the last few years, the clubbing of departments under various Demands has been rationalized. This has been done to streamline departmental spending, and to bring greater transparency, accountability and control in the Budget. It would also instill greater discipline in matters of re-appropriation and avoid large variations between the Budget provisions and actual expenditure. The Hon’ble Members will also get a clearer picture of the expenditure they are voting on.

84. I now proceed to present before this august House the Budget Estimates for the financial year 2010-11. The Financial Year 2009-10 opened with a deficit of Rs.602.41 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs.634.06 crore representing a transaction deficit of Rs.31.65 crore during the year on annual account. Under the Budget Estimates 2010-11, the Total Receipts (net of Public Debt) are projected at Rs.30,085.98 crore, of which Revenue Receipts are Rs.24,540.83 crore, while Capital Receipts (net of Public Debt) are Rs.5,545.15 crore. These signify, respectively, an increase of Rs.1,729.05, Rs.1,538.93 crore and Rs.190.12 crore over the corresponding projections in the Revised Estimates 2009-10. The Total Expenditure (excluding Repayments) under the Budget Estimates 2010-11 is projected at Rs.33,600.84 crore, of which Revenue Expenditure is Rs.28,482.64 crore, while the Capital Expenditure is Rs.5,118.20 crore. These signify, respectively, an increase of Rs.2,004.73, Rs.1,818.49 crore and Rs.186.24 crore over the corresponding projections in the Revised Estimates 2009-10. The Budget Estimates 2010-11 project a Revenue Deficit of Rs.3,941.81 crore and a Fiscal Deficit of Rs.8,815.64 crore. The Balance from Current Revenues for 2010-11 is projected to be Rs.345.82 crore. The Revenue Deficit is primarily on account of the impact of the 6th Pay Commission, with the annual pay increase impact for 2010-11 amounting to about Rs.2,600 crore, and the arrears of pay and pension amounting to about Rs.1,570 crore.

85. Hon’ble members would be glad to note that our Government has made investments on capital expenditure to the tune of Rs.17,879 crore between 2005-2010, compared to the capital expenditure of only Rs.8,398 crore during 2000-2005.
This Government, Speaker Sir, is totally dedicated to creating a bright future for our State.

86. Let me now indicate the sectoral allocations in the Budget Estimates 2010-11. The Agriculture and Allied sector is slated to receive Rs.1,073.62 crore, the Power sector is slated to receive Rs.4,642.71 crore, the Transport sector is allocated Rs.1,142.10 crore, the Irrigation sector is projected to receive Rs.1,616.49 crore, the Water Supply and Sanitation sector is slated to receive Rs.1,297.69 crore, the Urban Development sector is allocated Rs.1,447.14 crore, the Education sector, including Industrial Training and Technical Education, is projected to receive Rs.6,377.41 crore, the Health sector is slated to receive Rs.1,125.48 crore, the Social Justice and Empowerment including Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes sector is allocated Rs.2,167.15 crore, and the Rural Development and Panchayat sector is slated to receive Rs.956.17 crore.

87. As against the Annual Plan projections in the Budget Estimates 2009-10 at Rs.10,000 crore, revised further to Rs.10,400 crore, the allocation for the Annual State Plan 2010-11 is proposed at Rs. 10,500 crore. In addition to it, an outlay of Rs.1,363.58 crore for the Centrally Sponsored Schemes and other development plan schemes has also been included on the Plan side, boosting the composite Plan outlay in the Budget Estimates 2010-11 to Rs. 11,863.58 crore.

88. Let me confess, Sir, that the decision to come before this august House with a revenue deficit budget this year was not an easy one. It would have been an easy escape route for me to prepare a budget without deficit by suppressing expenditure. But the collective conscience of this Government does not allow such populist measures at the expense of the future of our people. It was a conscious decision of our Government not to curtail investment expenditure on the ongoing projects and important projects in the pipeline, in the long term interest of this State, and we have targeted a modest increase in plan expenditure for our Annual Plan 2010-11 accordingly. We do propose to exercise economy and restraint in general expenditure in the government departments, and, indeed, our Government has already adopted significant economy measures, but the pace of development of Haryana has to be maintained at all costs.

89. Our effort in this Budget has been to consolidate the gains that have been made by the State in the last five years. The budget deficit is within manageable limits and the measures for further financial discipline are likely to reduce its pitch further. Our tax revenue has already started recovering its normal growth, and can be expected to exceed the modest targets kept in the Budget proposals. It is also expected that the share in central taxes and other devolutions would go up during the year, as the implementation of revised pay structure across the country and payments of arrears are sure to increase the income tax receipts of Central Government. I, therefore, feel confident in assuring the House that we will be able to implement all our projected programs very successfully while achieving the targets fixed in the Budget. For this,
I solicit the active cooperation and support of all the Hon’ble Members of this august House, and through them, of all the proud citizens of Haryana.

CONCLUSIONS AND COMMENDATION

90. Before I conclude, I would like to acknowledge the untiring efforts and dedication put in and exhibited by the Finance Secretary and his colleagues in the Finance Department and the National Informatics Centre and its employees who persevered day and night to help me prepare and present these Budget proposals.

91. Hon’ble Speaker Sir, through you I want to extend the most solemn assurance to this House and to the people of Haryana at large, that we would summon all resources available to us and dedicate ourselves to the task of taking Haryana forward on the path of development at the same pace and with the same zeal that we have shown in the last five years.

92. Sir, with these words now I commend the Budget Estimates 2010-2011 to this House for its consideration and approval.

JAI HIND

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 10:00 A.M. on Thursday, the 11th March, 2010.

(The Sabha then was adjourned till 10:00 A.M. on Thursday, the 11th March, 2010.)